

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1823

उत्तर देने की तारीख 08 दिसम्बर, 2021

भारत नेट परियोजना का क्रियान्वयन

1823. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयां आ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ओडिशा राज्य में विशेषकर नवरंगपुर, मलकानगिरी और कोरापुर जिलों में ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है जहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है;
- (ग) ओडिशा सहित देश में उक्त परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा चिह्नित की गई ग्राम पंचायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवसिंह चौहान)

(क) देश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारतनेट परियोजना चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की गई है। दिनांक 01.11.2021 तक देश में कुल 1,66,088 ग्राम पंचायतों सेवा के लिए तैयार कर दी गई हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी/चट्टानी सहित) के कवर करने वाले देश के दूर-दराज कोनों में व्यापक रूप से फैली ग्राम पंचायतों तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में अभिगम में कठिनाई के कारण प्रभावित हुआ है।

(ख) ओडिशा में पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से चरण-1 में क्रियान्वयन के लिए 3810 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था जिनमें से दिनांक 01.11.2021 तक 3809 ग्राम पंचायतों सेवा के लिए तैयार कर दी गई हैं। ओडिशा में चरण-11 में राज्य सरकार में राज्य आधारित मॉडल क्रियान्वित किया गया है जिसके तहत योजना में शामिल 2946 ग्राम पंचायतों में से 2402 ग्राम पंचायतों सेवा के लिए तैयार कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त योजना में शामिल 43 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों सेटलाइट मीडिया पर सेवा के लिए तैयार की जा चुकी हैं। ओडिशा में कुल 6230 ग्राम पंचायतों सेवा के लिए तैयार हैं। भारतनेट परियोजना के तहत ओडिशा में 569 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जाना बाकी है जिनमें नवरंगपुर जिले में 29 ग्राम पंचायतें, मलकानगिरी जिले में 51 ग्राम पंचायतें और कोरापुट जिले में 51 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (ओडिशा सहित) विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(घ) दिनांक 30.06.2021 को भारतनेट परियोजना का दायरा ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर सभी बसे गांवों तक कर दिया गया था। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य अगस्त, 2023 है।

लोक सभा के दिनांक 08.12.2021 के अतारंकित प्रश्न सं. 1823 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतनेट परियोजना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा (दिनांक 01.11.2021 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	योजना में शामिल कुल ग्राम पंचायतों की सं.	सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की सं. जिनको सेवा के लिए तैयार किया जाना बाकी है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70	24	46
2	आंध्र प्रदेश*	13426	1708	11718
3	अरुणाचल प्रदेश	1796	749	1047
4	असम	2664	1499	1165
5	बिहार	8405	8298	107
6	चंडीगढ़	12	12	0
7	छत्तीसगढ़*	11682	8386	3296
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	36	2
9	गोवा#	191	0	191
10	गुजरात*	14287	13888	399
11	हरियाणा	6259	6082	177
12	हिमाचल प्रदेश	3226	403	2823
13	जम्मू और कश्मीर	4281	1055	3226
14	झारखंड*	4395	4049	346
15	कर्नाटक	6086	6083	3
16	केरल	978	978	0
17	लद्दाख	193	187	6
18	लक्षद्वीप	10	9	1
19	मध्य प्रदेश	22841	16698	6143
20	महाराष्ट्र*	28237	21247	6990
21	मणिपुर	2785	1436	1349
22	मेघालय	1791	625	1166
23	मिजोरम	763	452	311
24	नगालैंड	994	224	770
25	ओडिशा*	6799	6230	569
26	पुदुचेरी	108	98	10
27	पंजाब	13337	12668	669
28	राजस्थान	11352	8769	2583
29	सिक्किम	185	23	162
30	तमिलनाडु*§	12520	0	12520
31	तेलंगाना*	12769	5676	7093
32	त्रिपुरा	1021	711	310
33	उत्तर प्रदेश	59365	33858	25507

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	योजना में शामिल कुल ग्राम पंचायतों की सं.	सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की सं. जिनको सेवा के लिए तैयार किया जाना बाकी है
34	उत्तराखंड	7962	1629	6333
35	पश्चिम बंगाल	3348	2298	1050
	कुल	264176	166088	98088

* इन राज्यों में चरण-II को राज्य आधारित मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है।

\$तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारतनेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.03.2017 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार तमिलनाडु में भारतनेट के चरण-I को नहीं लागू किया था तथा राज्य की ग्राम पंचायतें चरण-II में राज्य आधारित मॉडल के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं।

#गोवा के पास अपना समान ब्रॉडबैंड नेटवर्क था और इस प्रकार भारतनेट परियोजना के चरण-I और चरण-II के तहत शामिल नहीं किया गया था।

नोट: दिल्ली में कोई ग्राम पंचायत नहीं है और इस प्रकार इसे भारतनेट परियोजना में शामिल नहीं किया गया है।
